[न रिश्वत लेंगे, न रिश्वत देंगे] मुंबई, शुक्रवार, 30 जनवरी 2026 । मूल्य 0.00, कुल पृष्ठ 4 [वर्ष: 12, डिजिटल अंक: 151, प्रधान संपादक : पवन जैन पदमावत] +91-9594542679 www.padmavatmedia.in padmavatmedia@gmail.com

सुविचार

फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला मनुष्य ही मोक्ष प्राप्त करता है।

दैनिक हिन्दी राष्ट्रीय डिजिटल समाचार पत्र

पदमावत मीडिया

Reg. No. MH180326353

जिला कलेक्टर की अध्यक्षता ... 03

डिजिटल संस्करण महाराष्ट्र व राजस्थान से प्रकाशित

04 आशान्वित ब्लॉक भीम में ...

खबर संक्षेप

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री से की मुलाकात

मटेरियल कंपोनेंट के तहत 825 करोड़ रुपये की राशि जारी होने पर जताया आभार

नई दिल्ली/जयपुर @ पदमावत मीडिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार देर रात नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। मुलाकात

के दौरान मुख्यमंत्री ने राजस्थान के लिए मटेरियल कंपोनेंट के अंतर्गत 825 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी किए जाने पर आभार व्यक्त किया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने इस संबंध में अगली किस्त का भुगतान शीघ्र करने का आश्वासन भी दिया। बैठक में प्रदेश में कृषि एवं ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही कृषक कल्याण को समर्पित योजनाओं की प्रगति, ग्रामीण अधोसंरचना के विकास और किसानों को अधिक लाभ पहुंचाने से जुड़े मुद्दों पर भी विचार-विमर्श हुआ।

ब्रह्माकुमारी राजयोग केन्द्र द्वारा विद्यार्थियों के लिए हेलो एग्जाम कार्यक्रम का आयोजन

संवाददाता : माणकमल भंडारी

भीनमाल @ पदमावत मीडिया। स्थानीय ब्रह्माकुमारी राजयोग केन्द्र के तत्वावधान में विद्यार्थियों के लिए हेलो एग्जाम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम आगामी बोर्ड एवं स्थानीय परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के मनोबल को सशक्त करने तथा परीक्षा के भय से मुक्त कराने के उद्देश्य से आयोजित होगा। कार्यक्रम के मीडिया प्रभारी माणकमल भंडारी ने बताया कि यह विशेष सेशन परीक्षा की पूर्व तैयारी के साथ-साथ विद्यार्थियों को मानसिक रूप से मजबूत बनाने पर केंद्रित रहेगा। कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को एकाग्रता, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए मार्गदर्शन दिया जाएगा। उन्होंने सभी अभिभावकों एवं विद्यालय प्रशासन से आग्रह किया है कि वे अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इस प्रेरणादायी सत्र में सहभागी बनने के लिए प्रेरित करें। राजयोग केन्द्र द्वारा विद्यार्थियों से भी अपील की गई है कि वे अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए इस कार्यक्रम में अवश्य भाग लें और अभी से इसकी तैयारी करें। कार्यक्रम में ब्रह्माकुमारी बी.के. गीता दीदी एवं युवा प्रभाग माउंट आबू के विख्यात फैकल्टी द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। यह कार्यक्रम 1 फरवरी, रविवार को प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक कचहरी रोड स्थित विद्यालय प्रांगण में आयोजित किया जाएगा।

राज्य स्तरीय ग्रीन ग्रोथ स्किल प्रतियोगिता में चयन पर अक्षरा पंचाल का सम्मान

उदयपुर @ पदमावत मीडिया। कल्याणपुर स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय की कक्षा 11 की छात्रा अक्षरा पंचाल को अजमेर में आयोजित राज्य स्तरीय ग्रीन ग्रोथ स्किल प्रतियोगिता में उदयपुर जिले का प्रतिनिधित्व करने पर विद्यालय स्तर पर सम्मानित किया गया।

संस्था प्रधान दिलीप सिंह राणावत एवं विद्यालय स्टाफ की उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम में अक्षरा को बधाई दी गई। अक्षरा ने ब्लॉक और जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त कर राज्य स्तर के लिए चयनित होकर जिले का नाम रोशन किया था। जिला स्तर पर उन्हें 11 हजार रुपये का नकद पुरस्कार भी प्रदान किया गया। विद्यालय परिवार और अभिभावकों ने अक्षरा की उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में पीएमश्री विद्यालय बन रहे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रतीक

बाल वाटिकाओं से लेकर डिजिटल लाइब्रेरी तक हो रहे दूरगामी नवाचार, 639 विद्यालय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित

पदमावत मीडिया
padmavatmedia@gmail.com

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शी सोच के अनुरूप तथा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रख रही है। इसी क्रम में प्रदेश के पीएमश्री (प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) विद्यालय आधुनिक, नवाचारी और गतिविधि-आधारित शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों को शैक्षणिक रूप से सक्षम बना रहे हैं।

पीएमश्री विद्यालय उत्कृष्ट प्रबंधन की अवधारणा पर आधारित हैं, जहां विद्यार्थियों को व्यावहारिक वातावरण के साथ आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इन विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाएं, प्रशिक्षित शिक्षक, नवाचार आधारित शिक्षण, मूल्यपरक अनुशासन और व्यावसायिक शिक्षा को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। पीएमश्री योजना के तहत राजस्थान में कुल 639 विद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है। पहले चरण में 402 तथा दूसरे चरण में 237 विद्यालयों में भवनों का कायाकल्प करते हुए आधारभूत संसाधनों का विस्तार किया गया है।

बाल वाटिकाओं का संचालन

प्रदेश के सभी 639 पीएमश्री विद्यालयों में बाल वाटिकाएं संचालित की जा रही हैं। प्रथम चरण के अंतर्गत अंश, अनमोल एवं आलोक वर्कबुक उपलब्ध कराई गई हैं तथा चाइल्ड फ्रेंडली फर्नीचर की व्यवस्था की गई है। सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों के माध्यम से अभिभावकों को भी शिक्षा प्रक्रिया से जोड़ा जा रहा है, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। बाल वाटिकाओं में एनटीटी शिक्षकों एवं सहायक कर्मियों की भी व्यवस्था की गई है।

डिजिटल लाइब्रेरी, ओ-लैब और एक्सपोजर विजिट

प्रदेश के 500 पीएमश्री विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी तथा 142 विद्यालयों में ओ-लैब स्थापित की गई हैं। सत्र 2024-25 में 623 विद्यालयों को 2492 विज्ञान एवं गणित किट उपलब्ध करवाई गई हैं। शैक्षणिक एवं औद्योगिक एक्सपोजर विजिट के माध्यम से विद्यार्थियों में व्यावहारिक ज्ञान और रोजगारोन्मुखी समझ विकसित की जा रही है।

आधुनिक प्रशिक्षण व्यवस्था

पीएमश्री विद्यालयों के शिक्षकों को आवासीय प्रशिक्षण, एबीएल किट तथा आईआईएम उदयपुर द्वारा नवाचार आधारित नेतृत्व प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है। जयपुर, सिरोही और उदयपुर में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने शिक्षण गुणवत्ता को नई दिशा दी है।

छात्राओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण

राज्य के सभी पीएमश्री विद्यालयों में संविधान कक्ष स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे विद्यार्थी लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूक हो सकें। इसके साथ ही छात्राओं को आत्मरक्षा एवं मार्शल आर्ट प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 144 विद्यालयों में सेनेटरी पैड इंसीनरेटर मशीनों की स्थापना भी की जा रही है।

पीएमश्री विद्यालयों की पहली बार राज्य स्तरीय रैंकिंग जारी

प्रदेश में पहली बार सभी 639 पीएमश्री विद्यालयों की राज्य स्तरीय रैंकिंग जारी की गई है। यह रैंकिंग 18 मानकों के आधार पर तैयार की गई है। रैंकिंग में पीएमश्री धावा (जोधपुर), पीएमश्री सावर (अजमेर), पीएमश्री मानपुरा माचेडी (जयपुर), पीएमश्री जोधकिया (हनुमानगढ़) और पीएमश्री रींगस (सीकर) शीर्ष पांच पीएमश्री विद्यालय रहे हैं।

कानून मंत्री जोगाराम पटेल के राजकीय निवास पर युवाओं का लगा तांता, TSP क्षेत्र की समस्याओं पर हुई गंभीर चर्चा

पदमावत मीडिया
padmavatmedia@gmail.com

रिपोर्ट : ललित पटेल

युवाओं ने नरेगा योजनांतर्गत कार्यरत ग्राम रोजगार सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं अन्य कार्मिकों को सिविल पोस्ट्स रूल्स 2022 में शामिल करने तथा विभिन्न भर्तियों से जुड़े मुद्दों को लेकर मंत्री से की मुलाकात

सलूंबर। सूबे के कानून मंत्री जोगाराम पटेल के जयपुर स्थित राजकीय निवास पर ऊरढ क्षेत्र से बड़ी संख्या में युवाओं का जमावड़ा देखने को मिला। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूंबर एवं सिरोही जिलों से आए युवाओं ने नरेगा योजनांतर्गत कार्यरत ग्राम रोजगार सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं अन्य कार्मिकों को सिविल पोस्ट्स रूल्स 2022 में शामिल करने तथा विभिन्न भर्तियों से जुड़े मुद्दों को लेकर मंत्री से मुलाकात कर अपनी समस्याएं रखीं। यह प्रतिनिधिमंडल सरदार पटेल सेना के राष्ट्रीय संयोजक कवि सुनील पटेल के नेतृत्व में जयपुर पहुंचा। युवाओं ने ऊरढ क्षेत्र में लंबित भर्तियों, संविदा कार्मिकों की स्थिति, आरक्षण तथा अन्य सामाजिक व रोजगार से जुड़े विषयों पर विस्तार से अपनी बात रखी। प्रतिनिधिमंडल ने अवगत कराया कि बांसवाड़ा जिले में वर्ष 2008 से महात्मा गांधी नरेगा योजनांतर्गत ग्राम रोजगार सहायक, लेखा सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं सहायक कर्मचारी के पदों पर कुल 152 संविदा कार्मिक कार्यरत हैं। इसी प्रकार बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं सिरोही जिलों में 350 से अधिक कार्मिक लंबे समय से अल्प मानदेय पर सेवाएं दे रहे हैं, जिन्हें लोक विज्ञापन के अभाव में संविदा सेवा नियम 2022 में शामिल नहीं किया गया। इस संबंध में न्यायालय में दायर याचिका पर 25 नवंबर 2025 को कार्मिकों के पक्ष में निर्णय पारित हो चुका है, इसके बावजूद अब तक आवश्यक कार्रवाई नहीं होने से कार्मिकों में असंतोष बना हुआ है।

कवि सुनील पटेल ने कहा कि सरदार पटेल सेना युवाओं के अधिकारों और हितों के लिए निरंतर संघर्ष करती रहेगी। उन्होंने सरदार पटेल जयंती पर राजकीय अवकाश, ऊरढ क्षेत्र में ओबीसी वर्ग को आरक्षण, माँ कुलदेवी आँजणा माताजी के साथ कार्यक्रम आयोजन सहित अन्य सामाजिक विषयों पर भी चर्चा की।

कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने युवाओं की बातों को गंभीरता से सुनते हुए आश्वस्त किया कि ऊरढ क्षेत्र के युवाओं की सभी समस्याओं के समाधान के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि न्यायालय के आदेशों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों से समन्वय किया जाएगा तथा युवाओं की मांगों को सरकार के समक्ष मजबूती से रखा जाएगा। मंत्री पटेल ने सरदार पटेल सेना के युवाओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे शीघ्र ही संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेकर माँ कुलदेवी आँजणा माताजी मंदिर सल्लाडा पहुंचकर आशीर्वाद लेंगे।

इस अवसर पर हेमंत पाटीदार चौखला, दिलीप पटेल पीपलोद, राजवीर भाई, कानजी पटेल वेजपुर सहित सैकड़ों युवा उपस्थित रहे।

पुलिस थाना श्रीनाथजी मंदिर की बड़ी कार्यवाही

एनडीपीएस एक्ट में गांजा, स्मैक, शराब, करीब 17 लाख रुपये नकद व वेन्यु कार जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार

पदमावत मीडिया
padmavatmedia@gmail.com

राजसमन्द। अवैध मादक पदार्थों की खरीद-फरोख्त के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस थाना श्रीनाथजी मंदिर ने बड़ी सफलता हासिल की है। कार्रवाई के दौरान अवैध गांजा, स्मैक, शराब, करीब 16 लाख 91 हजार 300 रुपये नकद तथा तस्करी में प्रयुक्त वेन्यु कार जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जला पुलिस अधीक्षक राजसमन्द ममता गुप्ता के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेन्द्र पारीक एवं वृत्ताधिकारी नाथद्वारा शिप्रा राजावत के निकटतम सुपरविजन में थानाधिकारी श्रीनाथजी मंदिर विक्रम सिंह के नेतृत्व में डीएसबी टीम द्वारा यह कार्रवाई की गई।

दिनांक 28 जनवरी 2026 को डीएसबी से सूचना प्राप्त हुई कि गिरिराजपुरा क्षेत्र में एक मकान में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री की जा रही है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और नियमानुसार तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान मकान के कमरे में रखे पलंग के नीचे से स्मैक की पुड़िया, बड़ी मात्रा में अवैध गांजा, देशी शराब के पव्वे, बीयर की बोतलें तथा लोहे की अलमारी से भारी मात्रा में नकद राशि बरामद की गई। इसके अतिरिक्त अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में प्रयुक्त वेन्यु कार को भी जब्त किया गया।

जांच में पाया गया कि आरोपी द्वारा गांजा, स्मैक एवं शराब बिना किसी वैध लाइसेंस अथवा अनुज्ञापत्र के अपने कब्जे में रखी गई थी। आरोपी अवैध मादक पदार्थों के स्रोत एवं नेटवर्क के संबंध में कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे सका। इस पर आरोपी को एनडीपीएस एक्ट एवं आबकारी अधिनियम की धाराओं में गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया गया। मामले का अग्रिम अनुसंधान थाना खमनोर द्वारा किया जा रहा है।

गिरफ्तार आरोपी सुरेन्द्र सिंह उर्फ सूर्या पिता कानसिंह, उम्र 38 वर्ष, निवासी गिरिराजपुरा, थाना श्रीनाथजी मंदिर, जिला राजसमन्द है।

जब्त सामग्री में 5 किलो 262 ग्राम गांजा, 0.93 मिलीग्राम स्मैक, देशी शराब व बीयर, 16 लाख 91 हजार 300 रुपये नकद तथा वेन्यु कार शामिल है।

इस कार्रवाई में पुलिस निरीक्षक विक्रम सिंह, उप निरीक्षक विशाल ग्वारिया, सहायक उप निरीक्षक गोपीराम, हेड कांस्टेबल उदयसिंह, महिला कांस्टेबल उषा, कांस्टेबल बलदेव, अनिल, अर्जुन, रायसिंह तथा चालक कांस्टेबल शम्भुसिंह शामिल थे।

पुलिस का कहना है कि अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान आगे भी पूरी सख्ती के साथ जारी रहेगा और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।

जिले में फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति को लेकर विभागवार समीक्षा बैठक आयोजित

कलक्टर ने अधिकारियों को दिए समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन के निर्देश

पदमावत मीडिया
padmavatmedia@gmail.com

सलूंबर। जिले में केंद्र एवं राज्य सरकार की प्रमुख फ्लैगशिप योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रगति की समीक्षा को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलक्टर अवधेश मीना की अध्यक्षता में विभागवार समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, स्वास्थ्य बीमा योजना, पालनहार योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, विद्युत, महिला एवं बाल विकास, कृषि, ग्रामीण विकास सहित अन्य प्रमुख योजनाओं की विभागवार विस्तार से समीक्षा की गई।

जिला कलक्टर ने प्रत्येक विभाग से योजना-वार प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए तथा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

बैठक के दौरान लाभार्थी चयन, लंबित प्रकरणों के निस्तारण, फील्ड स्तर पर निरीक्षण, जनसुनवाई से प्राप्त मामलों की स्थिति, पोर्टल अपडेट एवं अंतर-विभागीय समन्वय जैसे विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। जिला कलक्टर ने अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग, पारदर्शिता बनाए रखने तथा आमजन से निरंतर संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फ्लैगशिप योजनाएं आमजन के जीवन स्तर में सुधार लाने का सशक्त माध्यम हैं, इसलिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए निर्धारित समय सीमा में लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करें।

पुलिस थाना रेलमगरा की बड़ी कार्यवाही : ग्राम चौकड़ी हत्याकांड का खुलासा, अब तक 07 अभियुक्त गिरफ्तार

पदमावत मीडिया
padmavatmedia@gmail.com

राजसमन्द। पुलिस थाना रेलमगरा क्षेत्र के ग्राम चौकड़ी में 22 जनवरी 2026 को हुई मारपीट व हत्या की सनसनीखेज घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने त्वरित व प्रभावी कार्रवाई करते हुए मामले का खुलासा कर दिया है। इस प्रकरण में अब तक कुल सात अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है तथा शेष पहलुओं पर गहन अनुसंधान जारी है।

जिला पुलिस अधीक्षक राजसमन्द ममता गुप्ता के निदेशानुसार तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेन्द्र पारीक के सुपरविजन में वृत्ताधिकारी के नेतृत्व में गठित विशेष पुलिस टीम द्वारा इस हत्याकांड की गहन जांच की गई। जांच के दौरान हत्या में शामिल अभियुक्तों की पहचान कर चरणबद्ध तरीके से उनकी गिरफ्तारी की गई।

घटना के संबंध में सामने आया कि 22 जनवरी 2026 को शंकरसिंह निवासी चौकड़ी ट्रक लेकर फतेहनगर से अपने गांव पहुंचा और ट्रक को सड़क किनारे खड़ा किया। इस दौरान ट्रक की बॉडी विद्युत लाइन से टकरा गई, जिससे लाइन का तार टूट गया। इसी बात को लेकर मौके पर मौजूद कार सवार महेन्द्र कुमार भील निवासी मदारा तथा उसके साथी पवनसिंह व सुनील रंगास्वामी द्वारा ट्रक चालक से विवाद और गाली-गलौच की गई। विवाद बढ़ने पर ट्रक चालक ने अपने परिजनों को फोन किया, जिसके बाद देवराजसिंह, प्रेमसिंह सहित अन्य लोग लाठी व सरियों के साथ मौके पर पहुंचे और कार सवार व्यक्तियों पर हमला कर दिया। हमले के दौरान महेन्द्र कुमार भील खेतों की ओर भागा, लेकिन उसका पीछा कर पुनः मारपीट की गई, जिससे उसकी मौके पर ही हत्या हो गई। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए।

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, घायल पवनसिंह को अस्पताल भिजवाया गया तथा मृतक की बहन की रिपोर्ट पर हत्या का प्रकरण दर्ज कर जांच प्रारंभ की गई। पुलिस ने पहले चरण में देवराजसिंह, शंकरसिंह और प्रेमसिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया। इसके बाद निरंतर प्रयास करते हुए शेष चार अभियुक्तों संग्रामसिंह, कालुसिंह, विजेन्द्रपालसिंह उर्फ कान्हा तथा मोतीराजसिंह को भी गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार सभी अभियुक्त ग्राम चौकड़ी, थाना रेलमगरा, जिला राजसमन्द के निवासी हैं। प्रकरण में आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है तथा घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच जारी है।

पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरह के अपराधों में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

गिवअप अभियान का असर: भीलवाड़ा में 3 लाख 22 हजार 14 अपात्र लाभार्थी एनएफएसए सूची से हटे तो 2 लाख 55 हजार 317 पात्र व्यक्ति एनएफएसए सूची में शामिल हुए

पदमावत मीडिया
padmavatmedia@gmail.com

भीलवाड़ा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया गिव अप अभियान रोज नये कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। भीलवाड़ा जिले ने इस अभियान में अव्वल रहते हुए अब तक 246190 लोगों से ह्यगिव अपह्ल करवाकर ऐतिहासिक सफलता अर्जित की है। ईकेवाईसी के माध्यम से 75824 लोग भी एनएफएसए योजना से हटे हैं। इस प्रकार कुल 322014 अपात्र लोगों को एनएफएसए योजना से हटाया गया। इन अपात्र लोगो के हटने से 255317 पात्र किन्तु वंचित लोगों को एनएफएसए योजना में जोड़ने में जिले को सफलता मिली है। एक ओर जहां एनएफएसए योजना से हटाये लोगों पर वहन होने वाली खाद्य, गैस, बीमा, चिकित्सा सब्सिडी से बचत होगी वहीं दूसरी ओर नये एनएफएसए लाभार्थियों को इन चार योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। जिला रसद अधिकारी अमरेन्द्र कुमार मिश्र ने बताया कि ह्यगिव अपह्ल योजना के तहत चार पहिया वाहन मालिकों, सरकारी कार्मिकों, आयकर दाताओं तथा 01 लाख से अधिक वार्षिक आय वाले लोगों ने एनएफएसए लाभ का त्याग कर सामाजिक उत्तरदायित्व का परिचय दिया है। ह्यगिवअपह्ल अभियान ने समाज में जागृति पैदा की है एवं लोग भारी संख्या में ऑनलाईन एवं ऑफलाईन ह्यगिव अपह्ल कर सामाजिक कर्त्तव्य का निर्वहन कर मिसाल कायम कर रहे हैं। इस अभियान में समाज के हर वर्ग के लोगों, जनप्रतिनिधियों एवं सोशियल, प्रिन्ट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। खाद्य विभाग के कार्मिकों एवं उचित मूल्य दुकानदारों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विभाग ने एम.एस.पी. पर 100 क्विंटल से अधिक गेहूँ बेचने वाले लाभार्थी परिवारों की सूची उपलब्ध कराई है जिनकी जांच की जा रही है। वर्तमान में यह योजना 28फरवरी 2026 तक के लिए है। 28 फरवरी 2026 तक स्वेच्छा से गिव अप नहीं करने वाले अपात्र लाभार्थियों से 01 मार्च 2026 से 30 रुपए 57 पैसे प्रति किलोग्राम गेहूँ की दर से खाद्यान्न वसूली की जायेगी।

खबर संक्षेप

मध्यप्रदेश पुलिस की अवैध हथियारों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई

विगत 2 सप्ताह में 34 अवैध हथियार एवं सामग्री जब्त

भोपाल @ पदमावत मीडिया। मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा प्रदेश में कानून-व्यवस्था सुदृढ़

बनाए रखने तथा आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से अवैध हथियारों के निर्माण, संग्रहण, परिवहन एवं उपयोग के विरुद्ध निरंतर, योजनाबद्ध एवं प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी के परिणामस्?वरूप विगत 2 सप्ताह में प्रदेश के विभिन्?न जिलो में पुलिस ने अवैध हथियार रखने, हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाने एवं संगीन आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अंतरराज्यीय गिरोह के विरूद्ध कार्यवाही कर 34 फायर आर्म्स, जिंदा कारतूस, वाहन एवं अन्य सामग्री जब्त की है।

एसटीएफ ग्वालियर-दो आरोपी अवैध हथियारों सहित गिरफ्तार

एसटीएफ ग्वालियर इकाई ने मुखबिर की सूचना के आधार पर एक प्रभावी कार्रवाई करते हुए शिवपुरी क्षेत्र से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान आरोपियों के कब्जे से 03 पिस्टल एवं 04 जिंदा राउंड जप्त किए गए हैं।

शिवपुरी- अवैध हथियार निर्माण फैक्ट्री पर निर्णायक कार्रवाई

अवैध हथियारों के स्रोत को जड़ से समाप्त करने की दिशा में शिवपुरी जिले के थाना करैरा क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने प्राप्त सूचना के आधार पर अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पर दबिश देकर मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने फैक्ट्री से 07 अवैध हथियार, 05 जिंदा कारतूस सहित हथियार निर्माण में प्रयुक्त मशीनें, औजार एवं अन्य सामग्री जब्त की। जब्त की गई सामग्री की अनुमानित कीमत लगभग 2 लाख रुपये आँकी गई है। आरोपियों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट एवं अन्य धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है।

बड़वानी – अंतरराज्यीय गिरोह पर बड़ी कार्रवाई

थाना जुलवानिया पुलिस ने महाराष्ट्र के अहमदनगर (अहिल्यानगर) से चोरी कर लौट रहे 05 अंतरराज्यीय आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से 05 फायर आर्म्स, 03 जिंदा कारतूस, सोने-चांदी के आभूषण, नगदी एवं अन्य सामग्री सहित 38 लाख 91 हजार रुपये से अधिक की सामग्री जब्त की है। इसी प्रकार प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी अलग-अलग दिनों में अवैध हथियारों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई। ग्वालियर एवं दतिया जिलों में 05-05 अवैध हथियार, छतरपुर जिले में 03 अवैध हथियार, मुरैना जिले में 02 अवैध हथियार जब?त किए हैं। जबकि उज्जैन, सतना, सागर एवं जबलपुर जिलों में 01-01 अवैध हथियार जब्त किए गए हैं।

इन कार्रवाइयों से जिलों में अलग-अलग मामलों में सार्वजनिक स्थानों पर फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले आरोपियों को चिन्हित कर शीघ्र गिरफ्तार किया गया है। देशी कट्टे, पिस्टल (9टट, 32 बोर, 315 बोर), जिंदा राउंड, खाली खोखे, चाकू, खंजर सहित मोटरसाइकिल एवं कारें जब्त की गईं। अवैध हथियार निर्माण में प्रयुक्त मशीनें, औजार एवं अन्य सामग्री बरामद कर उन्हें निष्क्रिय किया गया।

मध्यप्रदेश पुलिस अवैध हथियारों एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त तत्वों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत निरंतर, कठोर एवं निष्पक्ष कार्रवाई कर रही है।

पेट्रोल डालकर सांड को जलाया

पाली @ पदमावत मीडिया। राजस्थान के पाली जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बेजुबान सांड को बेरहमी से पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया गया। जलता हुआ सांड आग के गोले की तरह गांव की गलियों में दौड़ता नजर आया। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना के बाद गांव में आक्रोश का माहौल है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है। यह घटना पाली जिले के पिपलिया कला गांव की है, जहां रात करीब 9:30 बजे सर्दी के कारण अधिकांश लोग अपने घरों में दुबके हुए थे। गांव की गलियां लगभग सुनसान थीं। इसी दौरान कुछ युवक अपने दोस्तों के साथ अलाव ताप रहे थे, तभी अचानक एक सांड जलता हुआ गांव की गली में दौड़ता नजर आया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सांड के शरीर पर आग लगी हुई थी और वह दर्द व घबराहट में इधर-उधर भाग रहा था।

अजित पवार के निधन से बदलेंगे राजनीतिक समीकरण?

महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर उस चौराहे पर आकर खड़ी हो गई है, जहां से सियासी जोड़-तोड़ वाले गठबंधन के साथ ही जीत-हार के अलग-अलग रास्ते नजर आ रहे हैं। दरअसल उप मुख्यमंत्री अजित पवार का एक विमान हादसे में आकस्मिक निधन न केवल एक प्रभावशाली नेता के एक युगा का अंत है, बल्कि इसके दूरगामी राजनीतिक प्रभाव भी दिखाई देने लगे हैं। 66 वर्षीय अजित पवार का यूं अचानक चले जाना उस समय हुआ है, जब महाराष्ट्र की राजनीति पहले से ही अस्थिर समीकरणों, टूटे गठबंधनों और बदले हुए सत्ता संतुलन से गुजर रही थी। वैसे तो अजित पवार का राजनीतिक जीवन जितना लंबा और प्रभावशाली नजर आता है, उतना ही विवादों और टकरावों से भरा भी रहा। जुलाई 2023 में उन्होंने अपने चाचा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के संस्थापक शरद पवार के खिलाफ बगावत कर महाराष्ट्र की राजनीति को झकझोर दिया था। आठ अन्य विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे और भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल होकर उन्होंने न केवल एनसीपी को दो हिस्सों में बांट दिया, बल्कि पवार परिवार की राजनीति में भी गहरी दरार डाल दी थी। यह फैसला शरद पवार के लिए राजनीतिक ही नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से भी बड़ा झटका माना गया था। तब अजित पवार का तर्क था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और महाराष्ट्र की प्रगति के लिए भाजपा के साथ जाना जरूरी है। लेकिन शरद पवार ने इसे सत्ता का दुरुपयोग बताते हुए जनता के बीच जाने का रास्ता चुना। 2023 के बाद से दोनों चाचाभतीजे अलग-अलग राजनीतिक राहों पर चल पड़े। 2024 के लोकसभा चुनावों में अजित

सनत जैन
पदमावत मीडिया
@padmavatmedia.in

पवार की एनसीपी कमजोर साबित हुई, लेकिन उसी वर्ष हुए विधानसभा चुनावों में उन्होंने 41 सीटें जीतकर खुद को एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर लिया। इसके उलट शरद पवार की एनसीपी (एसपी) केवल 10 सीटों पर सिमट गई। अजित पवार का निधन ऐसे समय हुआ है, जब वे एक बार फिर पूरी पार्टी की कमान संभाले हुए थे और जिला परिषद व पंचायत समिति चुनावों के लिए प्रचार में जुटे थे। माना जा रहा था कि इन स्थानीय चुनावों में वे अपने चाचा शरद पवार के साथ किसी समझौते की ओर बढ़ सकते हैं, लेकिन अब यह संभावना भी समाप्त हो गई है। वैसे इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि अजित पवार के अचानक यूं जाने के बाद सहानुभूति की लहर शरद पवार के पक्ष में जा सकती है, खासकर मराठा समुदाय के बीच।

यह अलग बात है कि महाराष्ट्र में मराठा राजनीति पहले से ही कमजोर पड़ती दिख रही है। खेती, सहकारिता, शिक्षा और बैंकिंग जैसे क्षेत्रों में मराठा वर्चस्व धीरे-धीरे घटा है। भाजपा के उभार के बाद यह भावना और मजबूत हुई है कि पारंपरिक मराठा नेतृत्व हाशिये पर जा रहा है। ऐसे में शरद पवार के लिए यह क्षण भावनात्मक और राजनीतिक दोनों रूप से अवसर लेकर आ सकता है। ग्रामीण महाराष्ट्र में अब भी मराठा समाज की पकड़ है और अजित पवार के निधन से उपजी सहानुभूति शरद पवार को फिर से प्रासंगिक बना सकती है। हालांकि सत्ता के गणित की बात करें तो अजित पवार के निधन से तत्काल सरकार पर कोई खतरा नहीं दिखता। दरअसल 288 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के पास 132 सीटें हैं और शिवसेना (शिंदे गुट) के 57 विधायक हैं। अजित पवार गुट की एनसीपी के 41 विधायक भले ही सरकार से अलग हो जाएं, फिर भी सरकार के पास बहुमत बना रहेगा। बहरहाल यहां यह नहीं भूलना चाहिए कि राजनीति केवल संख्या का खेल नहीं होती, भावनाएं और सामाजिक समीकरण भी उतने ही अहम होते हैं। अजित पवार लंबे समय से मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा पाले हुए थे। 2004 से ही वे खुद को उस पद के लिए उपेक्षित मानते रहे और यही निराशा अंततः विद्रोह में बदली। उनका निधन उस अधूरे सपने के साथ हुआ, जिसे वे कभी पूरा नहीं कर पाए। आज जब वे राजकीय सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं, महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा शून्य पैदा हो गया है। आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि अजित पवार की अनुपस्थिति में उनकी एनसीपी किस दिशा में जाती है और क्या शरद पवार इस सहानुभूति को राजनीतिक पुनरुत्थान में बदल पाते हैं। इतना तय है कि यह हादसा केवल एक नेता का अंत नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति के अगले अध्याय की शुरूआत भी है।

एसडीएम सराड़ा ने किया एसडीआरएफ और डीएमएफटी कार्यों का निरीक्षण

गुणवत्ता में लापरवाही पर जताई नाराजगी

सलूंबर @ पदमावत मीडिया। उपखंड अधिकारी सराड़ा ने कातनवाड़ा, चावण्ड और केजड़ में चल रहे एसडीआरएफ एवं डीएमएफटी कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सुनारिया और मांडवा के आंगनवाड़ी केंद्रों में छत मरम्मत कार्य तथा बाणकला उच्च माध्यमिक विद्यालय और चावण्ड बालिका विद्यालय में कक्षा कक्ष निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया गया। निरीक्षण के समय निर्माण कार्यों में उपयोग की जा रही सामग्री की गुणवत्ता और कार्य की धीमी गति को लेकर ठेकेदार पर नाराजगी व्यक्त की गई। उपखंड अधिकारी ने मौके पर ही खराब गुणवत्ता की बजरी हटाने और मानक के अनुरूप सामग्री का उपयोग सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। साथ ही निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। निरीक्षण के दौरान नायब तहसीलदार उपखंड कार्यालय सहित अन्य संबंधित कार्मिक भी मौके पर उपस्थित रहे।

बस ट्रेलर में घुसी, 4 लोगों की मौत

भरतपुर @ पदमावत मीडिया। भरतपुर में स्लीपर बस और ट्रेलर की भीषण टक्कर में मां-बेटे समेत 4 यात्रियों की मौत हो गई। 5 यात्री घायल हो गए। बस कासगंज (उत्तर प्रदेश) से जयपुर जा रही थी। इस दौरान सेवर पुल पर खड़े ट्रेलर में घुस गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस के परखच्चे उड़ गए। बस में फंसे यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। एक्सीडेंट सेवर थाना इलाके में आगरा-जयपुर नेशनल हाईवे पर बुधवार देर रात करीब 2:30 बजे हुआ। सेवर थाना के स्थ्र अवधेश ने बताया- सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची।

आरोप पत्र देरी से जारी करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध भी होगी कार्यवाही

जयपुर @ पदमावत मीडिया। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने कहा कि जल जीवन मिशन में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध शत-प्रतिशत कार्यवाही की जाएगी एवं लम्बित दोषी अधिकारियों को आरोप पत्र जारी किए जाए। आरोप पत्र देरी से जारी करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध भी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों को सीसीए 16 एवं 17 में आरोप पत्र जारी किए है उनमें भी आवश्यक कार्रवाई करते हुए शीघ्र कार्यवाही करने की जाए। जलदाय मंत्री जलदाय विभाग के सभागार में विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने विभागीय बजट घोषणा 2024-25 एवं 2025-26 की समीक्षा करते हुए कहा कि जिन घोषणाओं की निविदाएं अभी तक प्रक्रियाधीन है उन्हें 15 फरवरी तक कार्य आदेश देने की कार्रवाई की जाए। वरना इस कार्य में विलंब करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी।श्री कन्हैया लाल चौधरी ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में की जा रही जल आपूर्ति की समीक्षा करते हुए कहा कि नवसृजित नगर पालिका क्षेत्रों में शहरी मापदण्डों के अनुसार 100 एलपीसीडी के अनुसार योजनाए क्रियान्वित करें ताकि भविष्य में पेयजल को लेकर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहें। उन्होंने सतही जल से लाभान्वित जिलों में ग्रीष्मकाल से पूर्व पर्याप्त भण्डारण की व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए।जलदाय मंत्री ने जल जीवन मिशन के अन्तर्गत योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि मिशन के तहत बकाया घरेलू कनेक्शनों को निर्धारित लक्ष्य के अनुसार पूर्ण करावें ताकि राष्ट्रीय जल जीवन मिशन को पूर्णता रिपोर्ट भिजवाई जा सकें। उन्होंने कहा कि मिशन के तहत की जा रही निविदाओं में अनावश्यक देरी नहीं की जाए, और आगामी 15 दिवस में बकाया निविदाएं पूर्ण की जाए।

> जिन अधिकारियों को सीसीए 16 एवं 17 में आरोप पत्र जारी किए है उनमें भी आवश्यक कार्रवाई करते हुए शीघ्र कार्यवाही करने की जाए

राजसमंदः ग्राम उत्थान शिविरों में विभिन्न योजनाओं से हजारों ग्रामीण लाभान्वित

ग्रामीणों को शिविर में मिल रहा तारबंदी, डिग्गी, पाइपलाइन सहित विविध योजनाओं का लाभ

पदमावत मीडिया
padmavatmedia@gmail.com

राजसमंद। ग्राम-2026 के तहत जिले में 23 से 25 जनवरी 2026 तक आयोजित ग्राम उत्थान शिविरों के माध्यम से प्रशासन और विभागों द्वारा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की एक सशक्त तस्वीर सामने आई है। तीन दिवसीय इस अभियान के दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों की सक्रिय सहभागिता दर्ज की गई, जिससे शासन की योजनाओं को सीधे लाभार्थियों तक पहुँचाने में उल्लेखनीय सफलता मिली है।

कृषि विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इन तीन दिनों में कुल 23 शिविरों का आयोजन किया गया जिनमें 10,290 पुरुष एवं 5,426 महिलाएँ शामिल रहीं। यह सहभागिता दशार्ती है कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में योजनाओं के प्रति जागरूकता और विश्वास लगातार बढ़ रहा है।

कृषि विभाग के अंतर्गत किसानों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी एवं आवेदनों की स्थिति से अवगत कराया गया। तारबंदी, पाइपलाइन, फार्म पोंड, बैलों से खेती प्रोत्साहन योजना, फसल बीमा और एमएसपी से संबंधित हजारों किसानों को जानकारी दी गई। अब तक 9,314 किसानों को कृषि योजनाओं की जानकारी, 7,500 को एमएसपी, तथा 6,691 किसानों को फसल बीमा संबंधी जानकारी प्रदान की जा चुकी है। साथ ही सॉइल हेल्थ कार्ड, बीज वितरण और मिनी किट सत्यापन जैसे कार्यों में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

उद्यानिकी विभाग द्वारा ड्रिप, फव्वारा संयंत्र, सौर पंप, प्लास्टिक मल्च एवं पॉलीहाउस योजनाओं को लेकर व्यापक जागरूकता फैलाई गई। अब तक 4,283 लाभार्थियों को उद्यानिकी योजनाओं की जानकारी दी गई, जबकि सौर पंप एवं पॉलीहाउस से जुड़े नए आवेदन भी तैयार किए गए।

सहकारिता विभाग के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड, सहकारी ऋण, ब्याज अनुदान योजनाएँ, नए गोदाम निर्माण, डेयरी सहकारी समितियों के खाते खोलने तथा सहकारिता सदस्यता अभियान में बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए। सहकारी ऋण योजनाओं की जानकारी अब तक 3,275 लोगों तक पहुंचाई जा चुकी है। पशुपालन विभाग की गतिविधियों में भी उल्लेखनीय सहभागिता देखने को मिली। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, पशुओं की प्राथमिक चिकित्सा, कृमिनाशक दवा वितरण, टीकाकरण, कृत्रिम गभार्धान और गौशाला विकास योजना के माध्यम से हजारों पशुपालकों को लाभ पहुंचाया गया। केवल पशु चिकित्सा सेवाओं के अंतर्गत ही 11,541 पशुओं का उपचार एवं औषधि वितरण किया गया।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा श्इ-ॠअट-ॠ अभियान, दीनदयाल उपाध्याय सर्वे, स्वामित्व कार्ड वितरण तथा ग्राम पंचायत कार्यालयों की स्थापना जैसे कार्यों में तेज गति से प्रगति की गई। 6,667 स्वामित्व कार्ड वितरित किए जा चुके हैं।

इसके अतिरिक्त जल संसाधन, मत्स्य, उद्योग, ऊर्जा और राजस्व विभागों द्वारा भी अपनी-अपनी योजनाओं के प्रचार-प्रसार, पंजीकरण एवं आवश्यकताओं के चिन्हिकरण का कार्य किया गया। पीएम सूर्यघर योजना, मत्स्य संपदा योजना और युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत भी नए पंजीकरण दर्ज हुए। कुल मिलाकर, यह तीन दिवसीय शिविर अभियान प्रशासन और विभागों के समन्वित प्रयासों का परिणाम है, जिसने योजनाओं को कागजों से निकालकर सीधे आमजन तक पहुँचाने का कार्य किया। जिला प्रशासन ने आने वाले दिनों में भी इसी तरह जन-केन्द्रित शिविर आयोजित कर विकास कार्यों को और गति देने की प्रतिबद्धता जताई है।

शनिवार को यहाँ होंगे शिविरः

31 जनवरी को बरार, रीछेड़, गुंजोल, मचीन्द, मेहन्दुरिया एवं फरारा में ग्राम उत्थान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों के माध्यम से ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने के साथ-साथ विभिन्न विभागों की योजनाओं की जानकारी एवं लाभ उपलब्ध कराया जाएगा।

शिविरों में संबंधित विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहेंगे और ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी शिकायतों, मांगों एवं प्रस्तावों का निस्तारण करेंगे। साथ ही पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ने, लंबित प्रकरणों की समीक्षा करने तथा नए आवेदनों को स्वीकार करने का कार्य किया जाएगा।

नए भारत का नया कानून है 'जीरामजी' देगा 125 दिन के रोजगार की गारंटी

पदमावत मीडिया
padmavatmedia@gmail.com

राजसमंद। भारत की आत्मा गांवों में वास करती है। गांवों का विकास भारत का विकास हैं। गांवों के बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रमुख प्राथमिकता है। उन्होने भारत की आधारभूत संरचना को मजबूत करने के साथ-साथ रोजगार देने के लिए मनरेगा का नया उन्नत रूप विकसित भारत-जी राम जी (वीबी-जी राम जी) विधेयक 2025, लागू किया है। यह अधिनियम ग्रामीण परिवारों को 100 की जगह 125 दिन का गारंटीकृत रोजगार, टिकाऊ बुनियादी ढांचा, और 60 दिनों का 'नो-वर्क पीरियड' (खेती के व्यस्त सीजन के लिए) प्रदान करता है, जो 2047 तक ग्रामीण विकास को सुदृढ़ करेगा।

यह केवल मजदूरी नहीं, बल्कि जल संरक्षण, आजीविका, और बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जीपीएस, एमआईएस डैशबोर्ड, और एआई आधारित निगरानी का उपयोग किया जाएगा। ग्राम पंचायत स्तर पर योजनाओं को स्थानीय जरूरतों के अनुसार तैयार किया जाएगा।

यह अधिनियम मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर अथवा किसी भी स्थिति में कार्य की समाप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर किए जाने को अनिवार्य करता है। यद्यपि निर्धारित अवधि से अधिक विलंब होने की स्थिति में अनुसूची-द्वितीय में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार विलंब के लिए मुआवजा देय होगा, जिससे मजदूरी सुरक्षा को सुदृढ़ता और श्रमिकों को विलंब से संरक्षण होगा। इस अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी रोजगार को चार प्राथमिक विषयगत क्षेत्रों में टिकाऊ सार्वजनिक परिसंपत्तियों के सृजन के साथ स्पष्ट रूप से जोड़ा गया है।

यह अधिनियम ग्रामीण परिवारों के लिए प्रति वित्तीय वर्ष मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी को 125 दिनों तक बढ़ाता है और सशक्तिकरण, समावेशी विकास, योजनाओं के अभिसरण (कन्वर्जेस) तथा परिपूर्ण (सेचुरेशन) तरीके से सेवाद्दप्रदाय को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है जिससे समृद्ध, सक्षम एवं आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत की नींव मजबूत होती है। इससे पूर्व संसद ने विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025 पारित किया था, जिसने भारत के ग्रामीण रोजगार और विकास ढांचे में एक निर्णायक सुधार का मार्ग प्रशस्त किया है। यह अधिनियम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (महात्मा गांधी नरेगा) को प्रतिस्थापित करते हुए आजीविका सुरक्षा को सुदृढ़ करने वाला एक आधुनिक वैधानिक ढांचा प्रदान करता है।

यह अधिनियम सशक्तिकरण, विकास, कन्वर्जेंस और परिपूर्णता (सेचूरेशन) के सिद्धांतों पर आधारित ग्रामीण रोजगार को केवल एक

कल्याणकारी योजना से आगे बढ़ाकर विकास का एक एकीकृत माध्यम बनाता है। यह ग्रामीण परिवारों की आय सुरक्षा को सुदृढ़ करता है, शासन और जवाबदेही को आधुनिक बनाता है तथा मजदूरी रोजगार को टिकाऊ व उत्पादक ग्रामीण परिसंपत्तियों के सृजन से जोड़ता है जिससे समृद्ध एवं सक्षम ग्रामीण भारत की नींव अधिक मजबूत होती है। यह अधिनियम प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कम-से-कम 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान करता है, यद्यपि परिवार के वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हों। पूर्व में उपलब्ध 100 दिनों के रोजगार के अधिकार की तुलना में यह वृद्धि ग्रामीण परिवारों की आजीविका को सुरक्षा प्रदान करती है, काम को पहले से अनुमानित करती है और उनकी आय को अधिक स्थिर बनाती है। यह अधिनियम बुवाई और कटाई के सीजन के दौरान कृषि से संबंधित गतिविधियों के लिए कृषि श्रम की उपलब्धता आसान करने के लिए राज्यों को एक वित्तीय वर्ष में कुल 60 दिनों की समेकित विराम अवधि अधिसूचित करने का अधिकार प्रदान करता है।

श्रमिकों को मिलने वाले कुल 125 दिनों के रोजगार के अधिकार यथावत बने रहेंगे जिसे शेष अवधि में प्रदान किया जाएगा, जिससे कृषि उत्पादकता और श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के मध्य संतुलित समायोजन सुनिश्चित होता है। यह अधिनियम एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया गया है, जिसे राज्यों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अधिसूचित और क्रियान्वित किया जाएगा। केंद्र और राज्यों के बीच 60:40, पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 तथा विधानसभारहित केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100 प्रतिशत केंद्रीय वित्तपोषण का है। निधि राज्यवार मानकीकृत आवंटनों के माध्यम से प्रदान की जाएगी जो नियमों में निर्दिष्ट वस्तुनिष्ठ मानकों पर आधारित होगी, जिससे पूवार्नुमेयता, वित्तीय अनुशासन व सुदृढ़ योजना निर्माण सुनिश्चित होगा।

इस अधिनियम के अंतर्गत प्रशासनिक व्यय की अधिकतम सीमा को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दिया गया है। यह योजना विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है, जिससे बेहतर मानव संसाधन की उपलब्धता, प्रशिक्षण, तकनीकी क्षमता तथा मैदानी स्तर पर सहायता सुदृढ़ करने के साथ-साथ ग्रामीण रोजगार को राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं से जोड़ती है।

स्लीपर बस खड़े ट्रेलर से टकराई महिला सहित चार यात्रियों की मौत

जयपुर @ पदमावत मीडिया। राजस्थान के भरतपुर जिले में आगरा-जयपुर राजमार्ग पर बुधवार देर रात एक बस खड़े ट्रेलर से टकरा गई। इस हादसे में एक महिला समेत चार लोगों की मौत हो गई। उक्त बस उत्तर प्रदेश के कासगंज से जयपुर जा रही थी। पुलिस ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि सेवर पुलिस थाना इलाके में यह सड़क हादसा उस समय हुआ जब एक स्लीपर बस सड़क पर खड़े ट्रेलर से टकरा गई। दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से बस में फंसे यात्रियों को निकालकर बचाया गया। हादसे में मृत व्यक्तियों की पहचान उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के सतोवा गांव की गीता (38), उनके बेटे कान्हा (8), अलवर जिले के कठूमर निवासी बस चालक मुखन सिंह (28) और एक अन्य के रूप में हुई है। शुरूआती जांच में दुर्घटना का कारण घना कोहरा बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक ट्रेलर में खराबी आ गई थी जिस कारण बिना बैरिकेड या चेतावनी संकेतों के सड़क पर खड़ा था। कोहरे के कारण बस चालक को वह दिखा नहीं और हादसा हो गया।

खबर संक्षेप

राज्यपाल से कश्मीर के छात्र प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात

जयपुर @ पदमावत मीडिया। लोकभवन में गुरुवार को भारत दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत कश्मीर से आए छात्र प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल हरिभाऊ बागडे से मुलाकात की।

इस दौरान राज्यपाल ने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की आत्मा कश्मीर है और भारत की शक्ति उसकी विविधता में निहित एकता में है। राज्यपाल ने कहा कि भारत की संस्कृति विभिन्न प्रांतों की परम्पराओं, ऐतिहासिक स्थलों और प्राकृतिक विरासत से जुड़ी हुई है। भारत दर्शन कार्यक्रम का उद्देश्य भी इसी भावना को साकार करना है, ताकि देश के विभिन्न हिस्सों के युवा एक-दूसरे की संस्कृति, परम्परा और जीवनशैली को समझ सकें। उन्होंने कश्मीर के इतिहास, संस्कृति और परम्पराओं को भारत की आत्मा बताते हुए कहा कि सभी नागरिकों को राष्ट्रहित में सोच रखते हुए कार्य करना चाहिए। दसवीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल, श्रीनगर के साथ आए इस भारत दर्शन प्रतिनिधिमंडल में श्रीनगर, पुलवामा, बारामुला, कुपवाड़ा सहित विभिन्न क्षेत्रों के विद्यार्थी शामिल थे। विद्यार्थियों ने अपनी यात्रा के अनुभव साझा करते हुए भारतीय संस्कृति की विविधता और एकता पर अपने विचार रखे। राज्यपाल ने सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

किसान रजिस्ट्रेशन पोर्टल' के माध्यम से किसान गेहूँ विक्रय हेतु 1 फरवरी से करवा सकेंगे ऑनलाइन पंजीकरण

प्रदेश में 25 जून तक जारी रहेगी ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया

भीलवाड़ा/जयपुर। भारत सरकार द्वारा रबी विपणन सीजन 2026-27 हेतु गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य पच्चीस सौ पचासी रूपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। राज्य के किसान

अपनी उपज (गेहूँ) विक्रय हेतु पंजीयन दिनांक 1.02.2026 से 25.06.2026 तक स्वयं अथवा ई-मित्र के माध्यम से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान की वेबसाइट https://food.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध 'गेहूँ खरीद हेतु किसान रजिस्ट्रेशन पोर्टल' के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकेंगे। पंजीयन हेतु किसान के पास अद्यतन जन आधार कार्ड अनिवार्य है। किसान को उसके द्वारा विक्रय की गई उपज का भुगतान उसके जन आधार से जुडे हुए बैंक खाते में किया जाएगा। इसलिए किसान जिस बैंक खाते में भुगतान प्राप्त करना चाहता है उसे अपने जन आधार में जुड़वा लेंवे। पंजीकरण प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है। किसान पंजीकरण व अन्य खरीद सम्बन्धी जानकारी एवं समस्याओं के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14435 पर राजकीय कार्य दिवसों में प्रातः 10.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक सम्पर्क कर सकते हैं। किसान को खरीद संबंधी विभिन्न जानकारियों को एसएमएस के माध्यम से रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर समय-समय पर अवगत करवाया जायेगा। राज्य में रबी विपणन सीजन 2026-27 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीद का कार्य दिनांक 10 मार्च, 2026 से 30 जून, 2026 तक किये जाने का निर्णय लिया गया है। गेहूँ खरीद कार्य हेतु राज्य में एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, कुल 383 क्रय केंद्र स्थापित किये गये हैं। क्रय केन्द्रों की सूची खाद्य राजस्थान की वेबसाइट https://food.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। किसानों से गेहूँ खरीद कार्य भारतीय खाद्य निगम, राजफेड, तिलम संघ, नाफेड एवं एनसीसीएफ के साथ इस वर्ष से राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से भी किया जायेगा।

जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा की समीक्षा बैठक आयोजित, आवश्यक दिशा-निर्देश जारी

पदमावत मीडिया
padmavatmedia@gmail.com

सलूंबर। जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर अवधेश मीना की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में परिवहन विभाग, पुलिस विभाग, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगर परिषद, आरएसआरडीसी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में जिला कलेक्टर ने कहा कि सड़क सुरक्षा किसी एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि सभी विभागों और आम नागरिकों के सामूहिक प्रयास से ही सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण संभव है। उन्होंने निर्देश दिए कि जिले के प्रमुख मार्गों, ब्लैक स्पॉट्स और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की नियमित समीक्षा कर आवश्यक सुधारात्मक कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण किए जाएं।

बैठक में पिछले माह हुई सड़क दुर्घटनाओं की समीक्षा करते हुए उनके कारणों का विश्लेषण किया गया। दुर्घटना से संबंधित रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर प्रेषित करने के निर्देश दिए गए। बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, ओवरलोड और ओवरस्पीड वाहन चलाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने तथा गंभीर मामलों में लाइसेंस और परमिट निरस्त करने के निर्देश भी दिए गए। ओवरस्पीडिंग, शराब पीकर वाहन चलाने और नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने की घटनाओं पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। लोक निर्माण विभाग को सड़कों पर आवश्यक संकेतक, रिफ्लेक्टर, स्पीड ब्रेकर और रोड मार्किंग शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही जयसमंद पाल क्षेत्र में बस स्टैंड से पाल तक की सड़क को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए, ताकि पर्यटकों एवं आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

परिवहन विभाग को वाहन फिटनेस, ड्राइविंग लाइसेंस जांच और चालान प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य विभाग को सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति में त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पताल में आवश्यक संसाधन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही वाहन चालकों के लिए आंखों की जांच और स्वास्थ्य परीक्षण के लिए विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए।

पुलिस विभाग को प्रमुख चौराहों और हाईवे पर नियमित चेकिंग अभियान चलाकर यातायात नियमों की सख्ती से पालना कराने तथा जन जागरूकता के लिए प्रचार-प्रसार गतिविधियों को तेज करने के निर्देश दिए गए।

नगर परिषद आयुक्त को निजी बस स्टैंड को अन्य उपयुक्त स्थान पर स्थापित करने तथा शहर में सड़कों के किनारे निमार्णाधीन खुली नालियों को शीघ्र ढकने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही सड़क किनारे तय मापदंडों के विपरीत किए जा रहे निर्माण कार्यों को हटाने के भी निर्देश जारी किए गए।

निशुल्क नेत्र चिकित्सा एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर आयोजित

265 मरीजों की जांच, 36 मरीजों का ऑपरेशन हेतु चयन

पदमावत मीडिया
padmavatmedia@gmail.com

ब्रह्माकुमारी गीताबहन ने बताया कि राजयोग केन्द्र का यह 135वां नेत्र चिकित्सा शिविर है और अब तक ऐसे शिविरों के माध्यम से हजारों जरूरतमंदों के मोतियाबिंद ऑपरेशन कराए जा चुके हैं।

संवाददाता : माणकमल भंडारी

भीनमाल। अणदेश्वर वाटिका सोनी समाज भवन, भीमपुरा रोड मोदरान में निशुल्क नेत्र चिकित्सा एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन अणदाराम सेवा संस्थान मोदरान, ब्राह्मण स्वर्णकार युवा संगठन के सौजन्य से ब्रह्माकुमारी राजयोग केन्द्र एवं ग्लोबल अस्पताल आबूरोड के संयुक्त तत्वावधान में किया गया।

शिविर में 265 मरीजों के नेत्रों की जांच की गई, जिसमें से 152 मरीजों को निशुल्क चश्मे तथा 150 मरीजों को दवाइयों का वितरण किया गया। जांच उपरांत 36 मरीजों का मोतियाबिंद ऑपरेशन हेतु चयन किया गया, जिन्हें वाहन द्वारा ग्लोबल अस्पताल आबूरोड ले जाया गया, जहां उनका निशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा।

कार्यक्रम का शुभारंभ गुरुदेव अणदाराम महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। शिविर में पुलिस उप अधीक्षक शंकरलाल मसूरिया एवं बी.के. गीताबहन के आतिथ्य में कार्यक्रम संपन्न हुआ। पुलिस उप अधीक्षक शंकरलाल मसूरिया ने अपने संबोधन में इस पुनीत कार्य की सराहना करते हुए कहा कि नेत्र चिकित्सा एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन जैसे कार्य मानव सेवा की सर्वोच्च मिसाल हैं और अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ उठाना चाहिए।

ब्रह्माकुमारी गीताबहन ने बताया कि राजयोग केन्द्र का यह 135वां नेत्र चिकित्सा शिविर है और अब तक ऐसे शिविरों के माध्यम से हजारों जरूरतमंदों के मोतियाबिंद ऑपरेशन कराए जा चुके हैं। युवा संगठन जिलाध्यक्ष रमेश सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि संस्था द्वारा यह तीसरा शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें समाज का विशेष सहयोग रहा। शिविर के दौरान मोदरान गांव में जरूरतमंदों को 100 कंबल भी वितरित किए गए।

कार्यक्रम में मोहनलाल थूर, नरेशकुमार देता, महेन्द्रकुमार भीनमाल, घेवरचंद धुम्बड़िया, भूरचंद नोरा, जेठमल तिलोड़ा, राजमल पांथेड़ी, मुकेशकुमार पांचला, धनराज मोदरान, चम्पालाल धुम्बड़िया, मुलचंद भीनमाल, पुखराज चांदूर, शान्तिलाल जोड़वाड़ा, दिनेश, विक्रम, भरत, नरसाराम सहित अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। शिविर में सभी के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था जेठमल तिलोड़ा द्वारा की गई।

डूंगरपुर के दोवड़ा थाने के कांस्टेबल व हेड कांस्टेबल 1.50 लाख रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार

पदमावत मीडिया
padmavatmedia@gmail.com

जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी डूंगरपुर इकाई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस थाना दोवड़ा में पदस्थापित कांस्टेबल प्रकाशचन्द्र पटेल तथा हेड कांस्टेबल अशोक कुमार पाटीदार को 1 लाख 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अनुसार एसीबी डूंगरपुर को शिकायत प्राप्त हुई थी कि परिवादी को ऑनलाइन गेम के माध्यम से ठगी के झूठे आरोप में फंसाने की धमकी देकर उससे दो लाख रुपये की रिश्वत मांगी जा रही है। शिकायत के अनुसार 18 जनवरी 2026 को परिवादी को पुलिस वाहन में बैठाकर थाना दोवड़ा ले जाया गया, जहां उसके मोबाइल की जांच कर मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी गई। आरोप है कि मामले को दबाने और मोबाइल वापस देने के एवज में रिश्वत की मांग की गई।

परिवादी के भाई द्वारा आरोपी कांस्टेबल से मोबाइल पर संपर्क करने पर उसे थाने आकर मिलने के लिए कहा गया। इसके बाद एसीबी द्वारा मामले का सत्यापन कराया गया, जिसमें आरोपियों द्वारा 1.50 लाख रुपये रिश्वत लेने पर सहमति प्रकट की गई।

सत्यापन के पश्चात 28 जनवरी 2026 को एसीबी डूंगरपुर की टीम ने पुलिस उप अधीक्षक के नेतृत्व में ट्रैप कार्रवाई करते हुए कांस्टेबल प्रकाशचन्द्र पटेल एवं हेड कांस्टेबल अशोक कुमार पाटीदार को रिश्वत राशि लेते हुए गिरफ्तार कर लिया।

एसीबी अधिकारियों के अनुसार आरोपियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है तथा उनसे पूछताछ एवं अग्रिम अनुसंधान की कार्रवाई जारी है।

बैलों से खेती को बढ़ावा देने हेतु लघु एवं सीमांत कृषकों को 30 हजार रुपये वार्षिक प्रोत्साहन

पदमावत मीडिया
padmavatmedia@gmail.com

प्रतापगढ़। जैविक खेती की बढ़ती आवश्यकता और पारंपरिक कृषि पद्धतियों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने लघु एवं सीमांत कृषकों को बैलों से खेती के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के अंतर्गत बैलों से कृषि कार्य करने वाले पात्र कृषकों को 30 हजार रुपये प्रति वर्ष की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है।

योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए कृषक का लघु अथवा सीमांत श्रेणी का होना आवश्यक है। साथ ही कृषक के पास एक जोड़ी बैल होना अनिवार्य है, जिनका उपयोग नियमित रूप से कृषि कार्य में किया जा रहा हो। योजना का उद्देश्य रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों को कम करते हुए जैविक एवं पारंपरिक खेती को बढ़ावा देना है, जिससे भूमि की उर्वरता बनी रहे और पर्यावरण संरक्षण को भी मजबूती मिले।

आवेदन की प्रक्रिया

प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए कृषक नजदीकी ई-मित्र केंद्र अथवा स्वयं राजकिसान साथी पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के समय जन आधार कार्ड, जमाबंदी की

प्रति, 100 रुपये के नॉन-जुडिशियल स्टांप पर शपथ पत्र, बैलों के साथ फोटो तथा पशु चिकित्सक द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। योजना के तहत बैलों की आयु 15 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी के बाद पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर चयन किया जाएगा। चयनित कृषकों का समिति द्वारा भौतिक सत्यापन किए जाने के उपरांत प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा।

संयुक्त निदेशक कृषि विभाग बंशीधर मीणा ने बताया कि वर्तमान समय तक जिले में इस योजना के अंतर्गत कुल 8 लाख 40 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जा चुकी है। योजना के प्रभाव से कृषकों में जैविक एवं पारंपरिक खेती के प्रति सकारात्मक रुझान बढ़ा है और बैलों से खेती को पुनः अपनाने की दिशा में उत्साह देखा जा रहा है।

बकाया गृहकर, नगरीय विकास कर व विज्ञापन शुल्क के निस्तारण के लिए जोन स्तर पर वार्डवार कैंप, सिविल लाइन जोन में सख्त कार्रवाई

पदमावत मीडिया
padmavatmedia@gmail.com

जयपुर। नगर निगम जयपुर द्वारा जोन स्तर पर संपत्तिधारकों एवं अधिभोगियों की बकाया गृहकर, नगरीय विकास कर तथा विज्ञापन शुल्क से संबंधित आपत्तियों के त्वरित निस्तारण और वसूली के लिए वार्डवार आपत्ति निस्तारण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से संपत्तिधारक आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर नियमानुसार आपत्तियों का समाधान करवा सकते हैं तथा वर्तमान में लागू ब्याज व शास्ति में शत-प्रतिशत छूट का लाभ ले सकते हैं।

नगर निगम आयुक्त के निदेशानुसार एवं सिविल लाइन जोन के नेतृत्व में गुरुवार को बकाया करदाताओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई। इससे पूर्व मालवीय नगर जोन में भी इसी प्रकार की कार्रवाई की जा चुकी है।

सिविल लाइन जोन की राजस्व शाखा द्वारा जोन क्षेत्र में स्थित तीन संपत्तियों पर बकाया नगरीय विकास कर की वसूली के लिए कुर्की की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान दो संपत्तिधारकों ने जोन कार्यालय में उपस्थित होकर चेक के माध्यम से बकाया राशि जमा कराई, जिसके बाद उनकी संपत्तियों को कुर्की से मुक्त किया गया, जबकि एक संपत्ति को कुर्क कर सीज किया गया।

कुर्की एवं वसूली का विवरण इस प्रकार रहा—

तीन संपत्तियों पर कुल बकाया नगरीय विकास कर 27 लाख 32 हजार 960 रुपये पाया गया। दो

संपत्तियों से 5 लाख 50 हजार 538 रुपये की वसूली की गई। एक संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई जारी रखी गई।

नगर निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जिन संपत्तिधारकों पर लंबे समय से कर बकाया है, उनके विरुद्ध इसी प्रकार की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। आमजन से अपील की गई है कि वे समय पर अपने करों का भुगतान कर कानूनी कार्रवाई से बचें।

इन वार्डों में 30 जनवरी को लगेंगे शिविर

वार्ड 4, 5, 6 मुरलीपुरा जोन कार्यालय, मुरलीपुरा सब्जी मंडी के पास
वार्ड 50 घनश्याम बगरेट, सांगानेर स्टेडियम
वार्ड 130, 131, 132 रॉयल होटल के सामने, आगरा रोड
वार्ड 45, 46 सामुदायिक केंद्र, वरुण पथ मानसरोवर
वार्ड 68, 69, 70, 71 डिस्पेंसरी के पास सिंह द्वार
वार्ड 18, 20, 21, 22 झोटवाड़ा जोन कार्यालय, तारानगर-डी
वार्ड 30, 31 जोन कार्यालय तारानगर-डी, खिरणी फाटक
वार्ड 81, 83 मालवीय नगर जोन कार्यालय
वार्ड 90, 98 न्यू आतिश मार्केट

यह छूट दी जा रही है

बकाया गृहकर की पूरी राशि जमा करने पर मूल गृहकर पर 50 प्रतिशत तथा पेनल्टी पर 100 प्रतिशत छूट।

2007-08 से 2010-11 तक के बकाया नगरीय विकास कर में मूल राशि पर 50 प्रतिशत और ब्याज पेनल्टी पर 100 प्रतिशत छूट।

2011-12 से 2024-25 तक के बकाया नगरीय विकास कर में पेनल्टी पर 100 प्रतिशत छूट।

इन आपत्तियों का होगा निस्तारण

भूमि या निर्मित क्षेत्रफल से संबंधित आपत्ति
डीएलसी दर से संबंधित आपत्ति
नाम, पता या संपत्ति स्वामी से संबंधित आपत्ति
कर निर्धारण वर्ष से संबंधित आपत्ति
संपत्तिधारक शिविर स्थल पर पट्टा, रजिस्ट्री, साइट प्लान, स्वीकृत नक्शा, बिजली-पानी कनेक्शन से संबंधित दस्तावेज, शपथ पत्र एवं पहचान पत्र के साथ उपस्थित होकर आपत्तियों का निस्तारण करवा सकते हैं।

31 जनवरी से शुरू होगा भव्य धार्मिक महोत्सव

सलूंबर जिले में श्री राम मंदिर व मां हिंगलाज प्राण प्रतिष्ठा के साथ महारुद्र व सहस्त्रचंडी महायज्ञ का आयोजन

संवाददाता : ईश्वरलाल सुथार

सलूंबर @ पदमावत मीडिया। सलूंबर जिले की लांबी डूंगरी ग्राम पंचायत के अंतर्गत बलदेव भारती धूणी मठ, एमनिया पाड़ला मौजा सुआवतो का गुड़ा में 31 जनवरी से 11 फरवरी तक विशाल धार्मिक आयोजन का शुभारंभ होने जा रहा है। माघ शुक्ल पक्ष तेरस से फाल्गुन कृष्ण पक्ष नवमी तक आयोजित होने वाले इस भव्य महोत्सव में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, राज राजेश्वरी मां हिंगलाज प्राण प्रतिष्ठा के साथ महारुद्र एवं सहस्त्रचंडी महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। आयोजकों के अनुसार यह सलूंबर जिले का अब तक का सबसे भव्य राम मंदिर होगा।

यह आयोजन रामचंद्र गिरी के दिव्य सानिध्य एवं उनके शिष्य प्रताप गिरी के मार्गदर्शन में संपन्न होगा। आयोजन को लेकर क्षेत्र के एमनिया

पाड़ला, कुंडली, सुआवतो का गुड़ा, वाडा कुंडली, सलावता, देवली, गामड़ी, बांदरवाड़ा, डगार सहित आसपास के सभी गांवों एवं सर्व समाज को आमंत्रित किया गया है। आयोजन की तैयारियां दिन-रात अंतिम चरण में चल रही हैं।

मुख्य प्रतिष्ठाचार्य संजय गोविंद जोशी बड़ावली रहेंगे, जबकि उपाचार्य योगेश संजय मेहता सेरिया एवं राकेश व्यास होंगे। कार्यक्रम के दौरान गणेश पूजन, मंडप प्रवेश, दैनिक पूजा-अर्चना, मूर्ति लोकपाल, स्नान, आराधना, नित्य महाआरती एवं प्राण प्रतिष्ठा की समस्त वैदिक विधियां संपन्न करवाई जाएंगी।

9 फरवरी को भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें गाजे-बाजे, बग्गियों, घोड़ों के साथ क्षेत्र की महिलाएं कलश धारण कर नगर भ्रमण करते हुए मंदिर परिसर पहुंचेंगी। इसी दिन सायंकाल विराट भजन संध्या का आयोजन होगा, जिसमें क्षेत्र के प्रसिद्ध भजन गायक अपनी प्रस्तुतियां देंगे।

भक्तों के लिए विशेष व्यवस्थाएं

आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं के मनोरंजन हेतु डोलर, चकरी, झूले सहित बच्चों के लिए विभिन्न मनोरंजन साधन उपलब्ध रहेंगे। साथ ही 11 दिवसीय आयोजन में पधारने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए भोजन प्रसाद की समुचित व्यवस्था की गई है।

सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा

आयोजन की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर झल्लारा थाना अधिकारी जयकिशन फुलवरिया ने मय जाप्ता आयोजन स्थल का निरीक्षण किया तथा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। मठाधीश प्रताप गिरी ने सर्व समाज से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में पधारकर इस धार्मिक महायज्ञ का लाभ प्राप्त करें और आयोजन को सफल बनाएं।

खबर संक्षेप

जिला कलेक्टर श्री मेहता रहे ऋषभदेव दौरे पर

उपखंड स्तरीय कार्यालयों का किया वार्षिक निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश

उदयपुर @ पदमावत मीडिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सुशासन के संकल्प को साकार करने की दिशा में जिला कलेक्टर नमित मेहता जिले के ग्रामीण अंचलों के नियमित रूप से

दौरे कर रहे है। इसी क्रम में कलेक्टर मेहता गुरुवार को ऋषभदेव उपखंड के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने ऋषभदेव उपखंड कार्यालय, तहसील कार्यालय, उपकोष कार्यालय एवं पुलिस थाना ऋषभदेव का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर मेहता ने कार्यालयों की विभिन्न शाखाओं का अवलोकन किया। इस दौरान राजस्व संबंधित प्रकरण, ई-फाइल, संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों की गहन समीक्षा की। कलेक्टर मेहता ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संपर्क पोर्टल पर आमजन से जुड़े परिवादों का निस्तारण पूरी संवेदनशीलता और समयबद्ध तरीके से किया जाए। उन्होंने कार्यालय परिसरों में पुरानी पत्रावलियों व फाइलों को सुव्यवस्थित रूप से संधारित करने तथा रिकॉर्ड प्रबंधन को और बेहतर बनाने पर भी जोर दिया। निरीक्षण के दौरान ऋषभदेव उपखंड अधिकारी रामकरण सिंह, तहसीलदार आशीष सोनी, विकास अधिकारी पंकज कुमार आर्य सहित संबंधित विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

पुलिस थाना खेरोदा की बड़ी कार्यवाही

468.270 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा व स्कॉर्पियो गाड़ी जब्त

खेरोदा/उदयपुर @ पदमावत मीडिया। जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस थाना खेरोदा ने बड़ी सफलता हासिल की है। कार्रवाई

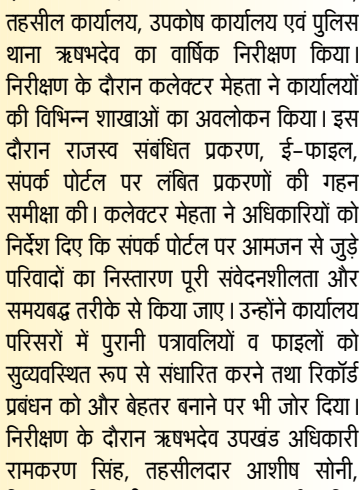

के दौरान 468.270 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा तथा तस्करी में प्रयुक्त एक स्कॉर्पियो गाड़ी जब्त की गई है। मामले में अज्ञात तस्करों की तलाश जारी है। जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर योगेश गोयल के निदेर्शानुसार तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खेरवाड़ा अंजना सुखवाल और वृत्ताधिकारी वल्लभनगर राजेन्द्र सिंह जैन के सुपरविजन में थानाधिकारी खेरोदा सुरेश विश्नोई के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। दिनांक 28 जनवरी 2026 को पुलिस थाना खेरोदा की टीम द्वारा नेशनल हाईवे 48 पर वाना चौराहे पर नाकाबंदी की गई थी। इसी दौरान मंगलवाड़ से उदयपुर की ओर जा रही एक काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी नाकाबंदी देखकर अचानक वाहन को रॉन्ग साइड में मोड़कर तेज गति से मंगलवाड़ की ओर भागने लगी। पुलिस टीम द्वारा तत्परता दिखाते हुए स्टॉप स्टिक का प्रयोग किया गया, जिससे वाहन का आगे का टायर क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बावजूद चालक वाहन को कुछ दूरी तक भगाता रहा, जिसे पीछा कर बमुश्किल रोका गया। वाहन रुकते ही चालक एवं सहचालक अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल की ओर फरार हो गए। स्कॉर्पियो की तलाशी लेने पर वाहन की सीटों के स्थान पर काले रंग के प्लास्टिक कट्टे भरे हुए पाए गए। जांच में कुल 22 कट्टों में भरा 468.270 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद किया गया। इसके अतिरिक्त वाहन में अलग-अलग नंबरों की पांच नंबर प्लेट भी मिलीं। इस संबंध में पुलिस थाना खेरोदा पर एनडीपीएस एक्ट एवं भारतीय न्याय संहिता 2023 की सुसंगत धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। मामले का अग्रिम अनुसंधान थाना कानोड द्वारा किया जा रहा है। फरार अभियुक्तों की पहचान एवं गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। इस कार्रवाई में थानाधिकारी सुरेश विश्नोई, हेड कांस्टेबल सुनील कुमार, कांस्टेबल बाबूलाल, कांस्टेबल दिनेश, कांस्टेबल कुलदीप, कांस्टेबल नितेश कुमार, कांस्टेबल मनोज कुमार तथा चालक कांस्टेबल नेमीचन्द शामिल थे।

संपूर्णता की ओर बढ़ता भीम

आशान्वित ब्लॉक भीम में संपूर्णता अभियान 2.0 का भव्य शुभारंभ

स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और स्वच्छता में शत-प्रतिशत संतृप्ति का लक्ष्य

पदमावत मीडिया
padmavatmedia@gmail.com

राजसमंद। नीति आयोग के निर्देशन में आशान्वित ब्लॉक भीम में संपूर्णता अभियान 2.0 का गुरुवार को भव्य शुभारंभ किया गया। अभियान का उद्देश्य स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, स्वच्छता, कृषि एवं पशुपालन से जुड़े प्रमुख संकेतकों में समयबद्ध शत-प्रतिशत संतृप्ति हासिल करना है, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित रूप से पहुंच सके।

अभियान के शुभारंभ अवसर पर जिला कलक्टर अरुण कुमार हसीजा, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बृजमोहन बैरवा, मुख्य आयोजना अधिकारी संजय शर्मा, स्थानीय उपखंड अधिकारी, विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, फ्रंटलाइन वर्कर्स तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

परिणामोन्मुखी और समन्वित पहल

जिला कलक्टर अरुण कुमार हसीजा ने कहा कि

संपूर्णता अभियान 2.0 एक समन्वित और परिणामोन्मुखी पहल है, जो योजनाओं को धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू करने में सहायक सिद्ध होगी। अभियान के माध्यम से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीबी उन्मूलन, कुपोषण की रोकथाम, संस्थागत प्रसव, टीकाकरण, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता और शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष फोकस किया जाएगा।

जिला परिषद सीईओ बृजमोहन बैरवा ने कहा कि अभियान की सफलता विभागीय समन्वय और जनभागीदारी पर निर्भर करती है। सभी विभाग मिलकर कार्य करेंगे तो अपेक्षित परिणाम निश्चित

रूप से प्राप्त होंगे। मुख्य आयोजना अधिकारी संजय शर्मा ने अभियान की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए बताया कि गतिविधियों को कैलेंडर के अनुसार चरणबद्ध तरीके से संचालित किया जाएगा।

14 अप्रैल तक चलेंगी गतिविधियां

अभियान की शुरूआत 30 जनवरी से ग्राम सभाओं के आयोजन के साथ होगी। ग्राम सभाओं में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा एवं पशुपालन से संबंधित संकेतकों की संतृप्ति के लिए प्रस्ताव पारित किए जाएंगे तथा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीबी उन्मूलन और स्वच्छता को लेकर शपथ दिलाई जाएगी। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में टीबी, एनीमिया एवं मातृ स्वास्थ्य से संबंधित जांच और जागरूकता शिविर आयोजित होंगे। 11 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय महिला एवं बालिका दिवस पर विद्यालयों और आंगनवाड़ी केंद्रों में किशोरियों के पोषण, स्वच्छता और सुरक्षित पेयजल पर विशेष सत्र होंगे।

28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर आंगनवाड़ी केंद्रों में सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता व्यवहार और बाल वृद्धि निगरानी से संबंधित गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर विशेष एएनसी पंजीकरण एवं परामर्श शिविर तथा गोद भराई कार्यक्रम होंगे। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर मानव और पशु टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा।

विश्व जल दिवस पर विशेष फोकस

22 मार्च को विश्व जल दिवस के अवसर पर विद्यालयों और आंगनवाड़ी केंद्रों में पेयजल सुविधाओं का निरीक्षण किया जाएगा तथा सुरक्षित जल भंडारण और स्वच्छता आदतों को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम होंगे।

जरूरतमंद तक योजनाओं की पहुंच प्राथमिकता

संपूर्णता अभियान 2.0 का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजनाएं केवल कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि वास्तविक रूप से जरूरतमंदों तक पहुंचें। यह अभियान संकेतक आधारित है, जिसमें स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित कर उनकी नियमित निगरानी और मूल्यांकन किया जाएगा।

जिला प्रशासन ने आमजन, जनप्रतिनिधियों, स्वयं सहायता समूहों और सामाजिक संगठनों से अभियान में सक्रिय सहभागिता की अपील की है। जनसहयोग और प्रशासनिक प्रतिबद्धता के साथ आशान्वित ब्लॉक भीम को संपूर्ण विकास का आदर्श मॉडल बनाने की दिशा में यह अभियान एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

नेवरी-चटवाड़ा सड़क-पुलिया बना भ्रष्टाचार का प्रतीक: निजी भूमि पर निर्माण, सीमांकन फील्ड बुक में बड़ा खुलासा

पदमावत मीडिया
padmavatmedia@gmail.com

विकास के नाम पर विनाश की नींव: बिना अधिग्रहण निजी जमीन पर सड़क-पुलिया, पीडब्ल्यूडी पर गंभीर आरोप

हातोद। हातोद तहसील के ग्राम नेवरीझचटवाड़ा को जोड़ने वाली सड़क एवं पुलिया निर्माण परियोजना अब विकास कार्य नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार, प्रशासनिक लापरवाही और सिस्टम की असंवेदनशीलता का उदाहरण बन चुकी है। वर्षों से चली आ रही शिकायतों, ग्रामीणों के विरोध और लगातार उठते सवालों के बीच अब प्रशासन द्वारा कराए गए सीमांकन की फील्ड बुक ने पूरे मामले की सच्चाई को दस्तावेजी रूप में उजागर कर दिया है। सीमांकन अभिलेखों में स्पष्ट उल्लेख है कि सड़क एवं पुलिया का निर्माण सर्वे नंबर 91 की निजी भूमि पर किया गया है, जबकि न तो इस भूमि का वैधानिक अधिग्रहण किया गया और न ही संबंधित भूमि स्वामी को किसी प्रकार का मुआवजा दिया गया। नेवरी पटवारी अनिल बांगर के अनुसार सर्वे नंबर 91 राजस्व अभिलेखों में निजी भूमि के रूप में दर्ज है। इसके बावजूद पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बिना नपती, बिना सीमांकन और बिना वैधानिक अनुमति के निर्माण कार्य कराया गया, जो भूमि अधिकार कानूनों का सीधा उल्लंघन है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस पूरे निर्माण कार्य में पीडब्ल्यूडी एसडीओ राजकुमार जैन, इंजीनियर राजेंद्र सोनी और ठेकेदार सुरेश माली की मिलीभगत से नियमों को दरकिनार कर परियोजना को अंजाम दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि यह निर्माण केवल भूमि विवाद का विषय नहीं है, बल्कि इसमें तकनीकी स्तर पर भी गंभीर अनियमितताएं हुई हैं। जमीनी अर्थवर्क से लेकर बेस लेयर, फाउंडेशन स्ट्रक्चर, स्लैब कास्टिंग, पुलिया की छत ऊंचाई, ड्रेनेज सिस्टम और जल निकासी चैनल तक हर स्तर पर गुणवत्ता मानकों की अनदेखी की गई। तकनीकी मानकों के अनुरूप कार्य न होने के कारण पुलिया संरचना की मजबूती और दीर्घकालिक स्थायित्व पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि गुणवत्ता नियंत्रण के नाम पर केवल कागजी खानापूर्ति की गई और वास्तविक निर्माण में भ्रष्टाचार का खुला खेल हुआ। इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर, पीडब्ल्यूडी मुख्य अभियंता और कार्यपालन यंत्री को लिखित शिकायतें की हैं, लेकिन आरोप है कि विभागीय स्तर पर जांच को गंभीरता से लेने के बजाय केवल औपचारिकता निभाई जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि जांच प्रक्रियाएं केवल फाइलों में सीमित होकर रह गई हैं और दोषियों को संरक्षण मिल रहा है। इस मामले में स्थानीय प्रशासन की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। ग्रामीणों का आरोप है कि हातोद एसडीएम विनोद राठौड़ द्वारा भी अब तक कोई ठोस हस्तक्षेप नहीं किया गया है, जिससे प्रशासनिक चुप्पी पर गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। सबसे गंभीर पहलू यह है कि यह तकनीकी रूप से दोषपूर्ण निर्माण अब केवल प्रशासनिक विवाद नहीं रहा, बल्कि पूरे नेवरी गांव के लिए पर्यावरणीय और जन-सुरक्षा का संकट बनता जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार पुलिया का ड्रेनेज सिस्टम अवैज्ञानिक तरीके से बनाया गया है। यदि निजी भूमि मालिकों ने अपनी जमीन पर भराव कर बाउंड्रीवॉल खड़ी कर दी, तो पुलिया की जल निकासी पूरी तरह अवरुद्ध हो जाएगी, जिससे वर्षा ऋतु में नेवरी गांव के जलमग्न होने का गंभीर खतरा पैदा हो जाएगा। यह स्थिति न केवल जनजीवन को प्रभावित करेगी, बल्कि कृषि भूमि, फसल, आवासीय क्षेत्र और बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा सकती है। पूर्व सरपंच बाबूलाल गेहलोत ने आरोप लगाया कि पीडब्ल्यूडी अधिकारियों और ठेकेदार की मिलीभगत से निजी भूमि में निर्माण कराया गया है। वहीं किसान प्रेमसिंह पिता कनीराम गेहलोत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बिना नपती और बिना सीमांकन सड़क एवं पुलिया का निर्माण उनकी निजी भूमि में किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन द्वारा वैधानिक मुआवजा या कानूनी समाधान नहीं दिया गया, तो वे अपनी भूमि पर भराव कर बाउंड्रीवॉल निर्माण करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और पीडब्ल्यूडी विभाग की होगी। गौरतलब है कि इस पूरे प्रकरण में जनप्रतिनिधियों की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। ग्रामीणों का कहना है कि विधायक मनोज पटेल और भाजपा नेता गणेश मिश्रा की चुप्पी ने प्रशासनिक तंत्र को और मजबूत संरक्षण प्रदान किया है। स्थानीय लोगों के अनुसार जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के कारण ही मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है और जनता की आवाज दबाई जा रही है। नेवरीझचटवाड़ा सड़क-पुलिया परियोजना अब विकास कार्य नहीं, बल्कि एक ऐसा उदाहरण बन चुकी है, जिसमें नियमों की अनदेखी, तकनीकी मानकों की हत्या, निजी संपत्ति अधिकारों का उल्लंघन और प्रशासनिक संवेदनहीनता एक साथ दिखाई दे रही है। यह मामला केवल सड़क निर्माण का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करता है कि आखिर विकास योजनाएं जनता के हित में बन रही हैं या भ्रष्टाचार के हित में। अब ग्रामीणों की मांग है कि इस पूरे प्रकरण की स्वतंत्र तकनीकी और प्रशासनिक जांच कराई जाए, दोषी अधिकारियों, इंजीनियरों और ठेकेदारों पर कानूनी कार्रवाई हो, निजी भूमि पर किए गए निर्माण का वैधानिक समाधान निकाला जाए और पुलिया व सड़क निर्माण की गुणवत्ता का तकनीकी ऑडिट कराया जाए, ताकि भविष्य में गांव को किसी बड़े संकट का सामना न करना पड़े।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर पोदावली में विराट हिन्दू सम्मेलन, सात गांवों की सहभागिता से बना ऐतिहासिक आयोजन

पदमावत मीडिया
padmavatmedia@gmail.com

राजसमंद। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राजसमंद जिले के पोदावली गांव में एक विराट हिन्दू सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। यह सम्मेलन सामाजिक समरसता, संगठनात्मक चेतना और सांस्कृतिक एकता का सशक्त प्रतीक बनकर सामने आया। आसपास के सात गांवों की सामूहिक सहभागिता ने आयोजन को ऐतिहासिक और प्रेरणादायक स्वरूप प्रदान किया।

सम्मेलन से पूर्व पोदावली, आत्मा, कुंवारिया, कनावदा, रातीतलाई, मादड़ी एवं दौलतपुरा गांवों के ठाकुर जी के सान्निध्य में भव्य शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा में राम दरबार, भारत माता तथा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की आकर्षक झांकियों ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। हजारों की संख्या में युवा वर्ग, मातृशक्ति एवं सज्जनशक्ति भगवा ध्वज हाथों में लेकर जयघोष करते हुए शोभायात्रा में शामिल हुए। पूरे मार्ग पर भगवामय वातावरण बना रहा। चौराहों और मार्गों को आकर्षक सजावट से सजाया गया तथा ग्रामीणों ने जगह-जगह पुष्पवर्षा कर शोभायात्रा का स्वागत किया। जय श्रीराम, भारत माता की जय और वंदे मातरम् के नारों से क्षेत्र गूंज उठा।

शोभायात्रा के आयोजन स्थल पर पहुंचने के पश्चात सम्मेलन का विधिवत शुभारंभ हुआ। मंच और पंडाल को महापुरुषों के चित्रों से सुसज्जित किया गया, जिससे वातावरण प्रेरणादायक और राष्ट्रभाव से ओतप्रोत बन गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संत अमितदास महाराज ने कहा कि हिन्दू सम्मेलन केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि समाज में संगठनात्मक भाव का बोध कराने वाला सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि जब समाज संगठित होता है, तभी राष्ट्र स्वतः सशक्त बनता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष समाज सेवा, राष्ट्र निर्माण और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के स्वर्णिम उदाहरण हैं। उन्होंने युवाओं से अपने संस्कारों को जीवन में उतारते हुए समाज और राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों का निष्ठा से निर्वहन करने का आह्वान किया।

मुख्य वक्ता सुरेंद्र सिंह राव ने अपने उद्बोधन में संघ की 100 वर्षीय यात्रा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संघ ने सदैव राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हुए समाज को दिशा देने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि हिन्दू समाज की एकता ही भारत की सबसे बड़ी शक्ति है और इस प्रकार के सम्मेलन समाज में सकारात्मक चेतना और आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं।

सम्मेलन के दौरान वक्ताओं ने सामाजिक समरसता, राष्ट्रभक्ति, संस्कृति संरक्षण एवं सेवा कार्यों पर विस्तार से विचार रखे। कार्यक्रम में महिलाओं और युवाओं की उल्लेखनीय उपस्थिति देखने को मिली, जो समाज में बढ़ती जागरूकता और सहभागिता का प्रमाण है। कार्यक्रम के समापन पर सामाजिक समरसता के संदेश के साथ महाप्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी वर्गों के लोगों ने एक ही पंगत में बैठकर प्रसाद ग्रहण किया।

आयोजन को सफल बनाने में स्थानीय क्षेत्र की युवाशक्ति, मातृशक्ति एवं सज्जनशक्ति ने अनुशासित रूप से व्यवस्थाएं संभालते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह सम्मेलन क्षेत्र में सांस्कृतिक चेतना और संगठनात्मक एकता का मजबूत संदेश देकर संपन्न हुआ।

राज्य भर में पीएम श्री चयनित राजकीय विद्यालयों में सम्पन्न हुआ विद्यार्थी एन्ड लाइन आकलन

पदमावत मीडिया
padmavatmedia@gmail.com

उदयपुर। पीएमश्री चयनित राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों के सीखने की गति एवं अधिगम परिणामों में सुधार लाने के उद्देश्य से अधिगम संवर्धन कार्यक्रम अंतर्गत कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थियों के लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की गयी है। इन विद्यालयों में संचालित उपचारात्मक शिक्षण के परिणामों का आंकलन करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा बेसलाइन एवं एन्डलाइन टूल का निर्माण कर उनके निर्देशन में राज्य में संचालित चयनित 628 पीएम श्री विद्यालयों की कक्षा 6, 8, 10 एवं 12 के तीन संकायों में चयनित विद्यार्थियों का डाइट के माध्यम से एन्डलाइन आकलन 29 जनवरी को सम्पन्न हुआ। पूर्व में बेसलाइन आंकलन 21 अगस्त 2025 को हुआ था।

आर एस सी ई आर टी द्वारा बेसलाइन एवं एंड लाइन आकलन के आंकड़ों का विश्लेषण कर उपचारात्मक शिक्षण की उपादेयता एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता को ज्ञात किया

एंड लाइन आकलन के आंकड़ों का विश्लेषण कर उपचारात्मक शिक्षण की उपादेयता एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता को ज्ञात किया जाएगा

जाएगा व जारी रिपोर्ट अनुसार जिले की स्थिति अनुसार कार्ययोजना बनाकर आवश्यक कार्य किये जावेंगे। यह राज्य स्तरीय एन्डलाइन आकलन श्वेता फगेरिया, निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के निर्देशन में प्रोफेसर बीना नाहर, एसोसिएट प्रोफेसर कपिला कंठालिया एवं टीम द्वारा सफलता पूर्वक पूरित किया गया।

कलक्टर हसीजा के नेतृत्व में एक और बड़ी उपलब्धि

लाडो प्रोत्साहन योजना में प्रदेश में द्वितीय स्थान पर पहुंचा राजसमंद, राष्ट्रीय पहल एसटीएफ में भी तीसरे स्थान पर

पदमावत मीडिया
padmavatmedia@gmail.com

राजसमंद। जिला कलक्टर अरुण कुमार हसीजा के नेतृत्व में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ हेमंत बिंदल की टीम के प्रयासों से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में जिले ने कुछ ही दिनों में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं। प्रभावी प्रशासनिक निगरानी, फील्ड-स्तरीय कार्यान्वयन और विभागीय टीम के समन्वित प्रयासों के चलते राजसमंद जिला प्रदेश स्तर पर अग्रणी जिलों में शामिल हुआ है।

लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत राजसमंद जिले ने प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जिले में जनआधार से जुड़े राजस्थान निवासी परिवारों की कुल 6514 जीवित बालिकाओं में से 6188 प्रकरणों का प्रथम किस्त के लिए सत्यापन पूर्ण किया जा चुका है। इस प्रकार योजना के अंतर्गत 95 प्रतिशत सत्यापन दर प्राप्त कर जिले ने राज्य स्तर पर अपनी मजबूत

उपस्थिति दर्ज कराई है। यह उपलब्धि बालिका सशक्तिकरण और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का स्पष्ट प्रमाण है।

गैर संचारी रोगों की रोकथाम में भी तीसरा स्थान: भारत सरकार की STF4STF (75 by 25) पहल, जो कि गैर संचारी रोगों की रोकथाम से संबंधित है, के अंतर्गत 31 दिसंबर 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार राज्य की समग्र उपलब्धि 60.94 प्रतिशत दर्ज की गई है। राजसमंद इसमें भी राज्य में तीसरे स्थान पर है। प्रदेश के 42 जिलों में से 16 जिले राज्य औसत से ऊपर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस सूची में झालावाड़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, झुंझुनूं और बूंदी शीर्ष पांच जिलों में शामिल हैं, जो जिले की निरंतर स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती को दर्शाता है।

उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसे गैर संचारी रोगों के नियंत्रण के क्षेत्र में राज्य का औसत फॉलो-अप रेट पिछले तीन महीनों में 38.61 प्रतिशत रहा है। हालांकि केवल 16 जिले ही राज्य औसत से ऊपर हैं, फिर भी राजसमंद का शीर्ष जिलों में शामिल होना यह दर्शाता है कि जिले में एनसीडी प्रबंधन को प्राथमिकता दी जा रही है। वहीं जिन जिलों में फॉलो-अप और कंट्रोल रेट कमजोर है, उनके लिए राज्य स्तर पर विशेष रणनीति बनाई जा रही है।

कलक्टर के निर्देशन में समन्वित प्रयासों का परिणाम:

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा योजनाओं की सतत मॉनिटरिंग, डेटा-आधारित निर्णय और फील्ड स्टाफ की सक्रिय भूमिका के चलते राजसमंद जिला स्वास्थ्य संकेतकों में निरंतर सुधार कर रहा है। विभाग आने वाले समय में इन उपलब्धियों को और सुदृढ़ करते हुए राज्य स्तर पर प्रथम पंक्ति में बने रहने के लिए प्रतिबद्ध है।

स्वत्वाधिकारी, संस्थापक, प्रकाशक एवं प्रधान सम्पादक : **पवन मॉगीलाल जैन उर्फ पवन जैन पदमावत, प्रधान कार्यालय** : गणेश नगर, कांदिवली वेस्ट, मुम्बई, महाराष्ट्र, भारत - 400067 से अमुद्रित ऑनलाईन प्रकाशित। **मो. नं.** : +91-95945-42679
e-mail :- padmavatmedia@gmail.com / Web : padmavatmedia.in (नोट : पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के चयन के लिए उत्तरदायी)। सभी विवादों का न्याय क्षेत्र मुम्बई, महाराष्ट्र होगा। उक्त ई-पेपर को अवैध रूप से छपवाना कानूनी अपराध हैं।